



वश्ववदियालय अनुदान आयोग (UGC) की नई पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वश्ववदियालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल **स्कीम फॉर ट्रांस- डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकॉनमी** (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy- STRIDE) की घोषणा की।

STRIDE के प्रमुख उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नहिति प्रतभा की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता नरिमाण करना, भारत की वकिसशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय वकिस हेतु **ट्रांस- डिसिप्लिनरी रिसर्च** को बढ़ावा देना है।
- मानवकी और मानव वजिज्ञान के संदर्भ में वशिष ध्यान देते हुए बहु-संस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परयोजनाओं को फण्ड प्रदान करना।

प्रमुख बदि

- STRIDE उन अनुसंधान परयोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होने के साथ ही स्थानीय रूप से आवश्यकता आधारित, राष्ट्रीय स्तर एवं वशिव स्तर पर महत्त्वपूर्ण हैं।
- यह अनुसंधान क्षमता नरिमाण के साथ-साथ बुनियादी व अनुपयुक्त तथा परिवर्तनकारी अनुसंधान का समर्थन करेगा जो समावेशी वकिस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय प्राथमकताओं में योगदान दे सकता है।
- यह मजबूत नागरिक समाज के नरिमाण हेतु नए वचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं तथा वकिस को समर्थन प्रदान करेगा।
- इस योजना से भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधानों को बढ़ावा मलैगा।
- कॉलेजों और वशिवदियालयों में ट्रांस- डिसिप्लिनरी रिसर्च कल्चर को मजबूत करने में सहयोग हेतु STRIDE के नमिनलखिति तीन घटक दिये गए हैं।
 - इसके अंतर्गत वशिवदियालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तथा नवाचार को प्रेरित करने के साथ ही युवा प्रतभाओं की पहचान की जाएगी। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु युवा प्रतभाओं की पहचान व समर्थन करके वविधि वषियों में अनुसंधान क्षमता का नरिमाण कया जाएगा। इसमें सभी वषियों पर अनुसंधान के लिये **1 करोड़ रुपए** तक का अनुदान दया जाएगा।
 - इस योजना के तहत भारत की वकिसशील अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिये सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान की मदद से समस्या नवारिण हेतु कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके तहत वशिवदियालयों, सरकार, स्वैच्छिक संगठनों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित कया जाता है। इसमें सभी वषियों पर अनुसंधान करने के लिये **50 लाख - 1 करोड़** तक का अनुदान दया जाएगा।
 - इसके तहत नधिकरिण के लिये पात्र शर्तों में शामिल हैं: दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, नृवजिज्ञान, मनोवजिज्ञान, स्वतंत्र कला (Liberal Art), भाषा वजिज्ञान, भारतीय भाषा एवं संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शकिषा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणजिय, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत वकिस। इस घटक के लिये उपलब्ध अनुदान के अंतर्गत एक उच्च शैक्षणिक संस्थान (Higher Educational Institutions- HEI) हेतु **1 करोड़ रुपए** और बहु संस्थागत नेटवर्क के लिये **5 करोड़ रुपए** तक है।

ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च

- यह नए वैचारिक, सैद्धांतिक, पद्धतगत नवाचारों के नरिमाण हेतु वभिन्न वषियों के क्षेत्र में कया जाने वाला एक प्रयास है जिसमें अनुशासन-वशिषिट दृष्टिकोणों से परे आम समस्या पर ध्यान दया जाएगा।
- शोध में ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयासों से हटकर व्यावहारिक उपयोग की आवश्यकता को संदर्भित कया जाएगा।
- यह अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से परे बौद्धिक रूपरेखा की एकता पर बल देता है और वभिन्न हतिधारकों को शामिल करने के लिये वषियों की सीमाओं से परे जाकर समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है।
- यह बहु और अंतर-अनुशासनात्मक अवधारणाओं के उपयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देता है।

वश्ववदियालय अनुदान आयोग

(University Grants Commission- UGC)

- 28 दसिंबर, 1953 को तत्कालीन शकिषा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शकिषा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापति एक स्वायत्त संगठन है ।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शकिषा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है ।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दलिली में अवस्थति है । इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूर में हैं ।

स्रोत- PIB

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/university-grants-commission>

